डिपो प्रबंधक एवं अन्य

बनाम

श्री एस. कृष्णा

(2018 की सिविल अपील संख्या 12244)

07 दिसम्बर 2018

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और एम.आर.शाह, जेजे.]

श्रम कानून:

सेवा समाप्ति - विभागीय जांच के क्रम में संविदा कर्मचारी की - विभागीय अपील और समीक्षा खारिज - औद्योगिक विवाद खारिज उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपने पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया और नियोक्ता को कर्मचारी को फिर से काम पर रखने और विस्तार करने का निर्देश दिया। डी की समाप्ति की तारीख से उसकी पुनः नियुक्ति की तारीख तक सेवा की निरंतरता का लाभ - एकल न्यायाधीश के आदेश की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पुष्टि की - अपील पर, उच्च न्यायालय ने तथ्यों पर ध्यान दिए बिना यांत्रिक रूप से निर्देश जारी किए व्यक्तिगत मामला- पहले मामले के तथ्य जिस पर उच्च

न्यायालय ने भरोसा किया था वह स्पष्ट था उच्च न्यायालय द्वारा सेवा की निरंतरता का अनुदान गलत था।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया :-

1. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने व्यक्तिगत मामलों के तथ्यों पर ध्यान दिए बिना, यांत्रिक रूप से विशेष रूप से पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए निर्देश जारी किए। एकल न्यायाधीश और खंडपीठ दोनों ने इस तथ्य को न समझकर भारी गलती की है कि वर्तमान मामले में कर्मचारी को विभागीय जांच करने और कदाचार के सभी आरोप साबित होने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। पिछला निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर पारित किया गया था क्योंकि उसमें बिना जांच किए समाप्ति आदेश पारित किया गया था। [पैरा 5 और 6] [|1266-सी-एफ]

2. अन्यथा भी एकल न्यायाधीश द्वारा समाप्ति को रद्द किए बिना ऐसा निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। निरंतरता की ज़मीन साधारण कारण से टिकाऊ नहीं थी जब तक कि समाप्ति का आदेश रद्द कर दिया गया है, निरंतरता प्रदान नहीं की जा सकती। निरंतरता तब प्रदान की जाती है जब सेवा में कोई अंतराल न हो यह सुनिश्चित करने के लिए समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। [पैरा 7] [1266-एफ-एच]

3. अपीलकर्ता ने चयन की नियमित प्रक्रिया के बाद अनुबंध पर वर्तमान प्रतिवादी की तरह कर्मियों की भर्ती की थी। आखिरकार संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाना है। प्रतिवादी जैसे व्यक्ति को सेवा की निरंतरता प्रदान करना। जो भी कदाचार करता पाया गया, उसे अन्य संविदा कर्मचारियों के समान दर्जा दिया जाएगा, जिनका रिकॉर्ड बेदाग है। इसलिए, एक बार जब प्रतिवादी को एक नई नियुक्ति दी गई और न तो समाप्ति और न ही नई नियुक्ति को मुद्दा बनाया गया, तो उच्च न्यायालय द्वारा सेवा की निरंतरता का अनुदान स्पष्ट रूप से गलत समझा गया था। [पैरा 8] [1267-ए-सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 12244/2018।

उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में 2013 की रिट अपील संख्या 1344 में पारित के निर्णय और आदेश दिनांक 24.07.2013 से।

गौरव बनर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता। श्रीहर्ष पिचरा, अर्जुन कृष्णन, आशीष तिवारी, सुश्री मनीषा सिंह, सुश्री राका, सीएसएन मोहन राव, तन्मय अग्रवाल, ए.एन. अरोड़ा, राज किशोर चौधरी, अधिवक्ता। उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय एम.आर.शाह, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में 2013 की रिट अपील संख्या 1344 में डिवीजन बेंच द्वारा में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से दिनांक 24.07.2013 के व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल प्रतिवादी-निगम-नियोक्ता ने इसे वर्तमान अपील प्राथमिकता दी है।

3. वर्तमान अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

ए. प्रतिवादी को एक अनुबंध चालक के रूप में नियुक्त किया गया था और वह अपीलकर्ता निगम के साथ काम कर रहा था।

बी. कि उनकी विभागीय जांच की गई।

सी. कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट के बाद उनकी सेवा समाप्त कर दी गई।

डी. विभागीय अपील भी खारिज हो गयी।

इ. क्षेत्रीय प्रबंधक के समक्ष समीक्षा याचिका भी गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दी गई।

एफ. इसके बाद मूल रिट याचिकाकर्ता ने औद्योगिक विवाद उठाया और इसे पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय 1, हैदराबाद द्वारा 2010 के औद्योगिक विवाद संख्या 93 में निर्णय और आदेश के तहत खारिज कर दिया गया।)

जी. इसके बाद कर्मकार-मूल रिट याचिकाकर्ता ने 2012 की रिट याचिका संख्या 5632 दायर करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

एच. विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिका को यह कहते हुए अनुमति दे दी कि मामला पुनः एकीकृत नहीं है और 2012 की रिट याचिका संख्या 2786 में दिनांक 29.02.2012 के विद्वान एकल न्यायाधीश के पहले के फैसले द्वारा कवर किया गया था। हालांकि निगम की ओर से एक प्रयास किया गया था पहले के निर्णय को इस आधार पर अलग करने के लिए बनाया गया था कि वर्तमान मामले में एक पूर्ण जांच की गई है, इस अंतर को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकृति नहीं मिली और केवल रिट याचिका संख्या 2786 में विद्वान

एकल न्यायाधीश के निर्णय पर विचार किया गया। 2012 और मामले के तथ्यों पर विचार किए बिना, मूल उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को सेवा में फिर से शामिल करने और सेवा की समाप्ति की तारीख से उसकी पुनः प्राप्ति की तारीख तक सेवा की निरंतरता का लाभ देने का निर्देश देकर रिट याचिका का निपटान करें। उस सेवा अवधि को छोड़कर, जिसके दौरान वह अनुपस्थित था,। हालाँकि, यह मौद्रिक लाभ के बिना था और इसे केवल नियमितीकरण के लिए गिनने के लिए निर्देशित किया गया था।

आई. विद्वान एकल न्यायाधीश के उपरोक्त आदेश की रिट अपील में डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि की गई थी।

4. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गौरव बेनर्जी ने प्रस्तुत किया है कि डिवीजन बेंच ने व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर विचार किए बिना और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने में भौतिक रूप से गलती की है और डिवीजन बेंच ने इस तथ्य की ठीक से सराहना नहीं की गई है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने सौहार्दपूर्ण ढंग से और तथ्यों के उचित अनुप्रयोग के बिना रिट याचिका का निपटारा केवल 2012 की रिट याचिका संख्या 2786 में विद्वान एकल

न्यायाधीश दिनांक 29 02.2012 द्वारा पारित आदेश पर भरोसा करते हुए किया, जो बिल्कुल भी लागू नहीं था। वर्तमान मामले में यह प्रस्तुत किया गया है कि मूल रिट याचिकाकर्ता को विभागीय जांच के बाद और विभागीय जांच में आरोप साबित होने और कदाचार साबित होने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने वाले डिवीजन बेंच द्वारा पारित मुख्य निर्णय और आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द करने और अलग करने की आवश्यकता है।

5. यहां अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और विद्वान डिवीजन बेंच द्वारा पारित मुख्य निर्णय और आदेश के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर विचार करने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस पर ध्यान दिए बिना व्यक्तिगत मामलों के तथ्यों के लिए, विशेष रूप से पहले के निर्णय दिनांक 29.02.2012 दीन रिट याचिका संख्या 2786/2012 पर भरोसा करते हुए यांत्रिक रूप से निर्देश जारी किए गए। हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच दोनों ने तथ्यों की सराहना न करके भौतिक रूप से गलती की है। वर्तमान मामले में विभागीय जांच होने और कदाचार के सभी आरोप साबित होने के बाद कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जबकि 2012 की रिट याचिका संख्या 2786 में ऐसा नहीं था।

6. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश का पिछला आदेश दिनांक 29.02.2012 उन मामलों के एक समूह में था, जहां कुछ मामलों में जांच किए बिना और अन्य में जांच किए बिना समाप्ति आदेश जारी किए गए थे, हालांकि इसका उल्लंघन किया गया था। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत. इस मामले को ध्यान में रखते हुए ऑपरेटिव आदेश के खंड 6 में निहित निर्देश में प्रावधान किया गया था कि ऐसे मामलों में जहां कोई जांच नहीं की गई थी, निगम कदाचार के आरोपों पर कानून के अनुसार जांच करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. अन्यथा भी, समाप्ति को रद्द किए बिना विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा ऐसा निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। निरंतरता का आधार साधारण कारण से टिकाऊ नहीं था, जब तक कि समाप्ति के आदेश को रद्द नहीं किया जाता। प्रथम सिद्धांत के रूप में, निरंतरता प्रदान नहीं की जा सकती। निरंतरता तब प्रदान की जाती है जब सेवा में कोई अंतराल न हो यह सुनिश्चित करने के लिए समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

8. एक और कारण है कि उच्च न्यायालय ए के फैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। यह सामान्य आधार है कि अपीलकर्ता ने चयन की नियमित प्रक्रिया के बाद अनुबंध पर वर्तमान प्रतिवादी जैसे कर्मियों की भर्ती की है। आखिरकार, अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाना है,

प्रतिवादी जैसे व्यक्ति को सेवा की निरंतरता प्रदान करना, जिसने कदाचार किया है, उसे उसी स्थान पर रखा जाएगा, जो अन्य अनुबंधित कर्मचारियों के समान है, जिनका रिकॉर्ड बिना किसी दोष के है। इसलिए, एक बार प्रतिवादी को एक नई नियुक्ति दी गई थी और न तो समाप्ति और न ही नई नियुक्ति को मुद्दे में रखा गया था, उच्च न्यायालय द्वारा सेवा की निरंतरता का अनुदान स्पष्ट रूप से गलत समझा गया था।

9. हमें निगम की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील की इस दलील में काफी हद तक योग्यता नजर आती है कि मामलों के पूरे बैच को एक सामान्य आदेश द्वारा तय करने में, विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ डिवीजन बेंच ने दुर्भाग्य से प्रत्येक व्यक्तिगत मामलों में तथ्यों की अनदेखी कर दी।

10. उपरोक्त कारण से, हम वर्तमान अपील की अनुमति देते हैं और तदनुसार 2013 की रिट अपील संख्या 1344 में दिनांक 24.07.2013 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के साथ-साथ 2012 की रिट याचिका संख्या 5632 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर देते हैं। कोई लागत नहीं।

कल्पना के.त्रिपाठी

अपील की अनुमति

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।